

मस्त जिला कोक्टर, राजस्थान ।

जन्मदिनांक:- 28-3-2000

प-58/राज-6/97/1

विषय:- कृषि भूमि के बँटवारे के प्रकरण शीघ्र निपटाने कायदा ।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53(2) के तहत काश्तकारों कृषि भूमि के आपसी सहमति या डिग्री के आधार पर बँटवारे के लिए प्रावधान है । इसके तहत राजस्थान काश्तकारी (राजस्वमण्डल) नियम, 1955 में नया प-58/राज-6/97/10 दिनांक 8.9.97 जारी किया गया है । इन नियमों के तहत कृषि जोत के सह कृषक अपनी जोत के विभाजन के अनुबंध निष्पादित कर जोतदार के समक्ष उसे प्रस्तुत करेंगे । सह कृषकों के बीच यदि कोई दावा चल रहा है उनमें विभाजन पर सहमति हो जाती है तो कृषकों की ऐसी सहमति के आधार पर न्यायालय डिग्री पारित कर देगा । राजस्व अधिकारी बँटवारे के ऐसे मामलों में सह-कृषकों के हिस्से की मात्रा के संबंध में कोई आपीत्त प्रस्तुत नहीं करेंगे ।

सह काश्तकारों से कृषि भूमि के बँटवारे के संबंध में काश्तकारी अधिनियम/नियम स्पष्ट एवं सरल प्रावधानों के बावजूद भी राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि इस तरह के काफी प्रकरण विचाराधीन है जिससे किसानों को अनावश्यक परेशानी होती है ।

उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि भूमियों के बँटवारे के संबंध में माह अप्रैल में नई जमाबंदियों के गठन के समय ऐसे सभी सहमति के मामलों को चिन्हित करें एवं काश्तकारों को विभाजन हेतु प्रेरित करें । जिला कोक्टर संबंधित डेल्टा पटवारी एवं गिरदावर को पाबन्द करें कि वे गांवों में जमाबंदियों के गठन के समय संयुक्त खाते से संबंधित काश्तकारों से चर्चा करें एवं सहमति के मामलों का पंजीकरण करें । यह जानकारी लेते कि क्या उक्त खाते की भूमि मौके पर सहमति के आधार पर पहले से बाँटी जा चुकी है अथवा नहीं ? यदि नहीं तो क्या वे सहमति के आधार पर बँटवारा करना चाहते हैं ? जोनों ही स्थितियों में मौके पर बँटवारा तैयार करवाया जाये । काश्तकारों के मध्य समझौता संबंधी चर्चा जोका तैयार कराया जाये । जिनो दावों तहसीलदार के समक्ष प्रेषित किया जाये तथा स्वीकार कराया जाये तबनुसार रिकार्ड में मूले नक्शा प्राप्त कराया कराया जाये ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि माह मई के प्रथम सप्ताह के अन्त तक ऐसे सभी मामलों पर बंटवारे के आदेश हो जाने चाहिए तथा मौके पर बंटवारा एवं नकशों में तरमीम का कार्य एक माह के अन्दर सम्पन्न कर इस प्रगति से इस विभाग को रोलिंग विवरण में अवगत कराया जाये।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाये।

भारतीय,

शिव कुमार शर्मा  
शासन उप सचिव

विवरण पत्र  
प्राप्त

भू-राजस्व अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत परस्तपर करार के आधार पर निस्तारित किए गये प्रकरणों का मासिक विवरण पत्र

जिले का नाम -----  
माह ----- वर्ष -----

क्र.सं०	खतबिल का नाम	गांवों की संख्या	कुल खतबिलदारों की संख्या
1.	2.	3.	4.

समझौते के आधार पर इच्छुक खतबिलदारों के खतबिलों की संख्या	मौके पर बंटवारा किये गए खतबिलों की संख्या	अवशेष प्रकरण
5.	6.	7.